



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल न्यायालय ६५ २५१६

क्रमा. 3146-PDR/15

रा०पुनरीक्षण प्र०क०:-

प्रस्तुत दिनांक :-



- 1-श्रीमती खुर्शीदबी पति अब्दुल बाकिर आयु-65 वर्ष,निवासी-बुरहानपुर
- 2-श्रीमती नूरजहां बी पति फरीद खां आयु-60वर्ष,निवासी-गुडी तह.व जिला खंडवा
- 3-श्रीमती खातून बी पति शेख अकबर आयु-58 वर्ष,निवासी-खारकलां,तहसील खालवा,जिला खंडवा

—याचिकाकर्तागण/अनावेदकगण

-विरुद्ध-

कुरषाडा

- 1-खालिक पिता हनीफ खां,मुसलमान,निवासी-ग्राम बेनपुरा,तहसील खंडवा,जिला

—आवेदक/प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

श्रीमान्

प्रत्यर्थी के द्वारा न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय खंडवा वृत्त जावर,के द्वारा रा०प्र०कमांक 35-अ/6 वर्ष-2010-11 में याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अंतरिम आवेदन अंतर्गत धारा 32 म०प्र०भू-रा०सं० सपठित धारा 151 सी०पी०सी० का निरस्त किये जाने संबंधी पारित आदेश दिनांक 6.04.2015 जिसकी जानकारी याचिकाकर्तागण को दिनांक 18.06.2015 को याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री आसिफ खान द्वारा अन्य प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित पर हुयी,तब अविलंब आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 10.07.2015 को आवेदन पेश किया,दिनांक 11.09.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अविलंब यह पुनर्विलोकन याचिका निम्न आधारों पर पेश करते है :-

श्रीमान् इन्दौर संभाग इन्दौर

दिनांक द्वारा दिनांक...14-09-2015

2015

02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3146-पीबीआर/15

जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-10-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-4-2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उनके समक्ष दो वसीयतनामों प्रस्तुत हुए हैं, अतः उन्हें प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार द्वारा इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि उन्हें प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि वसीयतनामों की संक्षिप्त जांच करने का अधिकार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत नायब तहसीलदार को प्राप्त है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p></p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	